IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का महिलाओं के स्वास्थ्य एवं सशक्तिकरण पर प्रभाव का अध्ययन

सुनील कुमार वर्मा
पी–एच.डी. शोधार्थी
राजनीति विज्ञान विभाग
एस.आर.टी. परिसर
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल
हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय(केन्द्रीय विश्वविद्यालय) श्रीनगर–गढ़वाल, उत्तराखंड
Email: vermasunilkumar65@gmail.com

सारांश

भारतीय ग्रामीण महिलाओं को स्वच्छ ईंधन प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एक ऐतिहासिक कदम है। इस योजना ने पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण भारत के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को मुफ्त रसोई गैस का कनेक्शन प्रदान किया गया है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों को स्वच्छ ईंधन प्रदान करना, वायु प्रदूषण में कमी एवं स्वास्थ्य संवर्धन करना है। ग्रामीण इलाकों में पारंपरिक ईंधन का प्रयोग भोजन बनाने के लिए किया जाता है जिससे वायु प्रदूषण एवं विभिन्न प्रकार कि श्वास सम्बन्धी बीमारियाँ होने कि संभावना बढ़ जाती है। यह योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन के लिए सब्सिडी देती है जिससे उन्हें स्वच्छ ईंधन उपलब्ध हो सके। इस योजना का महिलाओं के सशक्तिकरण एवं एक स्वस्थ समाज बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। स्वच्छ ईंधन का प्रयोग पर्यावरण को साफ रखने में मदद करता है। इस शोध प्रपत्र का उद्देश्य प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का महिलाओं के स्वास्थ्य एवं उनके सशक्तिकरण पर क्या प्रभाव पड़ा है, इस का अध्ययन करना है। इस शोध प्रपत्र में द्वितीयक श्रोतों का प्रयोग किया गया है।

महत्वपूर्ण शब्द– स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण, ईंधन, LPG, BPL, SECC , जन धन खाता।

परिचय

भारत देश दुनिया में आबादी के मामले में दूसरे स्थान पर आता है। भारत एक विकसित राज्य बनने कि ओर तेजी से अग्रसर है। साथ ही साथ इतना विकास होने के फलस्वरूप आज भी समाज के बहुत सारे लोग जीवन की जरूरी वस्तुएं जैसे रोटी, कपडा और मकान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जीवन को बनाये रखने के क्रम में सबसे पहला स्थान रोटी का आता है। भारत में आज भी ग्रामीण इलाकों में भोजन पकाने के लिए परंपरागत ईंधन जैसे लकड़ी, गोबर के उपले ,मिटटी का तेल ,कोयला आदि पर निर्भर है। ईंधन इकठ्ठा करने की अधिकांश जिम्मेदारी महिलाओं पर होती है। ग्रामीण महिलाओं को शुद्ध ईंधन की उपलब्धता बहुत कम है। अशुद्ध ईंधन का प्रयोग करने से महिलाओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जिससे उन्हें विभिन्न बीमारियाँ का सामना करना पड़ता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष 5 लाख मृत्यु अस्वच्छ ईंधन के प्रयोग से होती है जबकि अत्यधिक संख्या मे भोजन पकाने वाली महिलाएं स्वांस सम्बन्धी बीमारियों से ग्रसित हो जाती है। (रमन देवी, 2017) एक अध्ययन के अनुसार

लकड़ी ,गोबर के उपले जैसे पारंपरिक ईंधन के प्रयोग करने से एक घंटे में 400 सिगरेट पीने जितना नुकसान भोजन पकाने वाले व्यक्ति को होता है (रमन देवी, 2017)। स्वास्थ्य के जानकर कहते हैं कि लकड़ी आदि जलने से उठने वाले धुंए में हानिकारक तत्व पाए जाते हैं जो कई जानलेवा रोगों को जन्म देते हैं। भोजन पकाने की यह पूरी प्रक्रिया न सिर्फ स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालती है के बल्कि पर्यावरण को भी प्रदूषित करती है। महिलाओं की समस्याओं एवं अस्वच्छ ईंधन के प्रयोग से होने वाले हानिकारक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारम्भ किया। यह योजना का उद्देश्य स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन प्रदान करना है।

अध्यन का उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का महिलाओं के स्वास्थ्य एवं उनके सशक्तिकरण पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना है।

शोध प्रविधि– इस शोध प्रपत्र में द्वितीयक श्रोतों का प्रयोग किया गया है।

साहित्यिक पुर्नरावलोकन

उज्ज्वला गैस योजना के विषय में तथा महिलाओं के स्वास्थ्य एवं सशक्तिकरण पर पड़ने वाले इसके प्रभावों को समझने के लिए शोधार्थी ने विभिन्न समसामयिक लेखों, शोध प्रपत्रों का अध्ययन किया।

रमन देवी (2017) ने अपने शोध लेख **Pradhanmantri Ujjwala Yojana: Issues and Challenges** में विश्व स्वास्थ्य संगठन कि रिपोर्ट के आधार पर पारंपरिक ईंधन से होने वाले स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रभावों पर प्रकाश डाला है, इन्होंने पारम्परिक ईंधनों जैसे लकड़ी, गोबर के उपले आदि पर खाना पकाने से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को रेखांकित किया है। इस लेख के अनुसार भारत में गरीबों तक गैस पहुँचाना एक महत्वपूर्ण कदम है जिससे समय की बचत होगी तथा साथ ही स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

एन. अहमद ,श्लग्या शर्मा, डॉ. अंजनी कुमार सिंह (2008) ने सम्मिलित रूप से लिखें आपने अपने एक लेख **Pradhanmantri Ujjwala Yojana (PMUY) Step towards social inclusion in India** में यह रेखांकित किया है कि यह योजना गरीबों के लिए समावेशी उपक्रम कि ओर बढ़ता हुआ एक बड़ा कदम है। इस योजना के लागू होने से न सिर्फ गरीब महिलाओं को अस्वच्छ ईंधन एकत्रित करने से मुक्ति मिली है बल्कि भोजन पकाने में जो समय लगता है उसमें भी कमी आयेगी। इस शोध लेख के माध्यम से ये बताया गया है कि यह योजना क्या है ? किसको इसका लाभ मिलेगा ? इस योजना के लागू होने से क्या लाभ है ? इस योजना का महिला सशक्तिकरण, स्वस्थ समाज बनाने में एवं स्वच्छ पर्यावरण बनाने में योगदान की भी चर्चा की है।

विवेक आनंद (2018) ने अपने लेख **Two years of Ujjwala Yojana: Dalits in western UP and benefits despite resentment against centre on other issues** में योजना के जमीनी स्तर पर पड़ने वाले पभावों को रेखांकित करते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर व्यापक प्रभाव को स्वीकारा। इन्होने अपने लेख में जमीनी स्तर पर किये गए सर्वे के आधार पर महिलाओं की इस योजना के पक्ष में मुखर प्रतिक्रिया को सामने रखा है। इस शोध लेख में योजना के बारे में व्यापक चर्चा कि गई है।

कुंदन पाण्डेय ,जीतेन्द्र प्रियरंजन शाहू और पुरुषोत्तम ठाकुर (2018) ने अपने एक सम्मिलित शोध लेख **Ujjwala scheme: Are cleaner cooking fuels affordable and accessible?** में इस योजना को परिदृश्य बदलने वाली योजना बताया, लेकिन गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए गैस सिलेंडर को पुनः भरवाने कि असमर्थता को प्रकाश में लाते हुए इस योजना कि आलोचना की। यद्यपि इन्होने महिलाओं के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव से इसे जोड़ा और इस बात पर भी चर्चा किया कि यह योजना गर्भवती महिलाओं के लिए वरदान साबित हुई है।

Amose, T. and Sreedevi, N. (2017) ने अपने समीक्षा लेख **An Economic Assessment To Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY) Of Central Government of India** में इस योजना के सामाजिक आर्थिक तत्वों,

व्यवसाय, आय, शिक्षा, स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ा है इसकी चर्चा की गई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, वित्तमंत्री अरुण जेटली एवं केन्द्रीय तेल मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के टिप्पणियों को भी दिखाया है एवं रसोई गैस के मांग और उपभोग कि भी चर्चा की गई है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

ग्रामीण महिलाओं को स्वच्छ ईंधन प्रदान करने की दिशा में उठाया गया सबसे महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारम्भ किया। इस योजना के माध्यम से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 5 करोड़ परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य था जिसे 3 साल में यानि कि 2019 तक पूरा किया जाना था बाद में इस योजना का लाभ 8 करोड़ करोड़ परिवारों तक पहुँचाने का लक्ष्य 2020 तक रखा गया। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे परिवार की महिला के नाम से गैस कनेक्शन जारी किया जाता है। इस योजना के तहत लाभार्थी को गैस कनेक्शन मुफ्त दिया जाता है किन्तु गैस चूल्हा एवं पहली बार गैस को भराने का खर्च लगभग 1500 रुपये लाभार्थी को देने होते हैं। यदि लाभार्थी इस खर्च को वहन करने में असमर्थ है तो उसके लिए इस खर्च को चुकाने के लिए क़िस्त कि भी सुविधा दी जा सकती है जिसे बाद में सब्सिडी के माध्यम से भरपाई कर ली जाती है। लाभार्थी को तब तक सब्सिडी नहीं मिलती है जब तक उसका गैस चूल्हा/स्टोव एवं पहली बार गैस भरने का खर्च पूरा न हो जाये। जब यह पूरा हो जायेगा तो लाभार्थी को सब्सिडी का लाभ उसके बैंक खाते में जाने लगेगा।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ पाने के लिए आवश्यक प्रक्रिया एवं दस्तावेज

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की 18 साल से अधिक उम्र की महिला के नाम से गैस कनेक्शन जारी किया जाता है। सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना 2011 कि सूची में जिन परिवारों के नाम है उनके परिवार कि महिला के नाम से गैस कनेक्शन जारी किया जाता है। इस योजना के लिए आवेदन फॉर्म प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कि वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है या अपने नजदीकी एल.पी.जी विक्रय केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के लिए गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे परिवार का राशन कार्ड, सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना 2011 की सूची का फोटो कॉपी, पासपोर्ट साइज़ फोटो, आधार कार्ड, राष्ट्रीय बैंक का खाता, राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित स्वघोषणा पत्र जैसे जरूरी दस्तावेज लगते हैं। साथ ही साथ यह भी जरूरी होता है कि उस परिवार में पहले से कोई गैस कनेक्शन किसी अन्य सदस्य के नाम से न हो।

लाभार्थी को फॉर्म भरते हुए यह बताना पड़ता है कि 14.2 किलोग्राम का कनेक्शन चाहिए या 5 किलोग्राम का कनेक्शन चाहिए। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को मात्र कनेक्शन फ्री दिया जायेगा जबकि गैस स्टोव और पहली बार गैस भरवाने के खर्च को लाभार्थी को स्वयं देना पडता है और यदि लाभार्थी इसे देने में असमर्थ है तो उसे क़िस्त कि सुविधा भी दी जाती है जो उनकी सब्सिडी से काटी जाएगी जब यह पूरा हो जायेगा तो लाभार्थी कि सब्सिडी उसके खाते में जाने लगेगी।

इस योजना को लागू करने का उद्देश्य

1. महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना
2. स्वच्छ ईंधन प्रदान करना
3. परंपरागत ईंधन के प्रयोग से होने वाले स्वास्थ्य सम्बन्धी बीमारियों से बचाने के लिए
4. वायु प्रदूषण कम करने एवं पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभ

इस योजना से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन मिलता है जिससे अब वे स्वच्छ एवं धुंवा रहित ईंधन का प्रयोग कर सकेंगे। इस योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने 8000 करोड़ रुपये का अपने बजट में प्रावधान किया है। साथ में अमीर लोगों से अपनी गैस सब्सिडी छोड़ने का अनुरोध किया है।

जिससे यह योजना अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। इस योजना के लागू होने से ग्रामीण महिलाओं का जो समय पारंपरिक ईंधन लकड़ी, गोबर के उपले, फसलों के अपशिष्ट आदि इकठ्ठा करने में लगता था वह अब किसी अन्य सामाजिक आर्थिक कार्य में लगता है जिससे उनके सामाजिक आर्थिक स्तर में सुधार हुआ है। ग्रामीण महिलाओं को पारंपरिक ईंधन से भोजन पकाने में बहुत सारे धुंए का सामना करना पड़ता था जिससे उन्हें स्वांस सम्बन्धी, फेफड़े से सम्बंधित, आँख सम्बन्धी एवं कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बना रहता था। घर के अन्दर वृद्ध, गर्भवती महिला और बच्चें हैं तो उन पर ये हानिकारक धुंआ अत्यधिक खतरनाक प्रभाव डालता है। इस योजना में गैस कनेक्शन महिला के नाम से ही जारी होता है। लाभार्थी महिला का राष्ट्रीय बैंक का खाता रसोई गैस कनेक्शन से जोड दिया जाता है जिसमें गैस की सब्सिडी दी जाती है जो दोबारा गैस भरवाने में काम आती है। सब्सिडी महिला के बैंक खाते में आने से परिवार में उसकी भागीदारी निर्णय लेने में बढ़ जाती है और जो महिला पहले घर के कामों में ही लगी रहती थी। अब वह अपने घर के आँगन से निकल कर बाजार तक सब्सिडी का रुपये निकलने के लिए जाती है जिससे उसकी पहुँच न सिर्फ बाज़ार तक हुई है बल्कि उनका इसी बहाने सशक्तिकरण भी हो रहा है। किसी भी समाज को प्रगति करने के लिए उसका स्वस्थ रहना अति आवश्यक है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से महिलाओं, बच्चों एवं घर के वृद्धों के स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। पारंपरिक ईंधन के प्रयोग को बंद करके अब गरीबी रेखा से नीचे के ग्रामीण परिवार रसोई गैस का प्रयोग करते हैं जिससे हमारे पर्यावरण को भी स्वच्छ बनाने में मदद मिली है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कि व्यावहारिक चुनौतियाँ

इस योजना में लाभार्थी के चयन करने के लिए मात्र BPL सूची एवं SECC सूची 2011 का प्रयोग किया गया है जबकि बहुत सारे ऐसे परिवार भी हैं जो इन दोनों सूचियों में नाम न होने से उनको गैस कनेक्शन नहीं मिल पाता है। सरकार जो सब्सिडी लाभार्थी के बैंक खाते में डालती है उसे सीधे तेल एवं प्राकृतिक गैस कम्पनी को दे तो लाभार्थी पर इसका बोझ कम पड़ेगा और लाभार्थी जल्दी–जल्दी गैस को दोबारा भरवाने के लिए उत्साहित रहेगा। पहले तो लाभार्थी को सब्सिडी सहित गैस के खर्च का प्रबंध करना पड़ता है, फिर वही सब्सिडी उसके बैंक खाते में आती है जिससे समय और धन दोनों की हानि होती है। बहुत सारे रसोई गैस कनेक्शन लाभार्थी पर्याप्त धन का प्रबंध न होने से दोबारा गैस नहीं भरवा पाते हैं। सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए कि जितने गैस कनेक्शन जारी हुए हैं। उनमें से कितने लाभार्थी दोबारा गैस भरवा रहे हैं। सरकार ने महिलाओं को गैस उपयोग करने के लिए जागरूक करने की व्यवस्था की है। रसोई गैस पर भोजन पकाते समय क्या –क्या सावधानियाँ बरतनी है तथा आग लगने पर उसे कैसे बुझाना है। इन सब बातों की जानकारी देने के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया गया हैं।

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने महिलाओं को स्वच्छ ईंधन प्रदान कर उन्हें धुंए भरी जिंदगी से स्वतंत्रता दिलाई है। यह योजना गरीब महिलाओं के लिए वरदान साबित हुई है। अब महिलाओं को भोजन पकाने से जो समय बचता है उसे वें अपने जीवन के किसी अन्य महत्वपूर्ण कार्य में लगा सकती हैं जिससे उनका सामाजिक आर्थिक विकास हो सकता है। इस योजना ने महिलाओं के स्वास्थ्य एवं सशक्तिकरण पर बहुत सकारात्मक प्रभाव डाला है। इस योजना ने न सिर्फ ग्रामीण महिलाओं को स्वच्छ ईंधन प्रदान किया है बल्कि पर्यावरण को भी स्वच्छ बनाने में हमारी मदद की है। महिलाओं को भोजन पकाने में न सिर्फ आसानी हुई है बल्कि उन्हें धुंए में भोजन पकाने एवं लकड़ी ,गोबर के उपले बनाने जैसी पारंपरिक ईंधन को एकत्रित करने से भी मुक्ति मिल गई है। स्वस्थ समाज एवं स्वच्छ पर्यावरण बनाने में इस योजना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस योजना ने स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन के नारे को सही चरित्रार्थ कर दिया है। यह योजना गरीब परिवार में रोशनी बनकर आई है। इस योजना को बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाया गया है। योजना बहुत अच्छी है पर जमीनी स्तर पर कुछ समस्याएं इसे लागू करने में आ रही हैं।

संदर्भ सूची

1. Anand. V. (28 May 2018). Two Years of Ujjwala Yojana: Dalits in Western U.P. land benefits resentment against centre on other issues. First Post

2. Devi, R. (2017). Pradhan Mantri Ujjwala Yojana : Issues and challenges. International Journal Of Academic Research and Development, 2, 705-706.

3. N. Ahmad, Sharma, S. et al . (2018). Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY) Step towards Social Inclusion in India. International Journal of trend un Research and Development, 5, 46-49.

4. Pandey, K. et al (3 Feb 2018). Ujjwala Scheme : Are cleaner cooking fuels affordable and accessible ? Down to Earth.

5. T. Amose and Sreedevi N. (2017). An Economic Assessment To Pradhan Mantri \Ujjwal Yojana (PMUY) Scheme Of Central government Of India. International Journal of Current Research, 9, 60747-60750.

6. https://www.india.gov.in/spotlight/pradhan-mantri-ujjwala-yojana#tab=tab-1
7. http://petroleum.nic.in/sites/default/files/pmuy.pdf